

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—402/2015/75 (2015/00291)

1. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री भागचन्द, जाति रावत, निवासी मकान नं० जी-80-81, गणेश गुवाड़ी, ए-ब्लॉक, पंचशील नगर, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर जिला अजमेर ।
2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ-12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013.

उपस्थित:—

1. श्री एन०एस०राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोंडेंट संख्या 1.
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 2.

निर्णय

दिनांक:—14.9.2018

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ-12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013 के विरुद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लाडपुरा, तह० व जिा अजमेर अवस्थित वर्किंग खाता संख्या 149 नया 160 पुराना के वर्किंग खसरा नंबर 719 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वा, एवं 43/1295 रकबा 00-16-10 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3-04-00 बीघा भूमि के मूल खातेदार मानसिंह पुत्र दूलसिंह, जाति रावत रहे हैं, जिनके स्वर्गवास के बाद जरिये विरासत नामांतरण संख्या 43 दिनांक 11.9.1998 के द्वारा उनकी एकमात्र विधिक वारिस पुत्री श्रीमती रामी पुत्री मानसिंह जाति रावत के नाम खातेदारी स्वीकृत की गई । जिन भूमियों को अन्य कृषि भूमियों के साथ श्रीमती रामी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.1.2007 को अपीलांट के हक में विक्रय कर भौतिक आधिपत्य प्रदान कर दिया गया । इस प्रकार अपीलांट उक्त वर्णित भूमि पर कय दिनांक से आज दिवस तक काबिज काश्त होकर उसके उपयोग-उपभोग में चली आ रही है किन्तु विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमियों के संबंध में रिकार्ड एवं मौके की जांच किये बिना अपीलांट की खातेदारी भूमियों को आदेश दिनांक 27.9.2013 से अन्य कृषि भूमियों के साथ

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तांतरण करने के आदेश पारित किये । अधीन न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्ट्र की जाकर रेस्पो को तलब किया गया । रेस्पो के उपस्थित होने तथा अधीन न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांतस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांत की खातेदारी भूमि है । उक्त तथ्य की जानकारी रेस्पो संख्या 1 तहसीलदार अजमेर के माध्यम से विद्वान जिला कलक्टर को रही है इसके उपरांत भी आदेश दिनांक 27.9.2013 पारित किये जाने से पूर्व अपीलांत को किसी प्रकार की सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया । विद्वान वकील अपीलांत ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्थान भू-राजस्व अधीन 1956 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रक्ष्य में जिलाधीश, अजमेर द्वारा किसी भी भूमि को किसी भी विभाग/व्यक्ति के हक में आवंटन/नियम/हस्तांतरण किये जाने से पूर्व विधिक प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकार्ड एवं मौकी की जांच के साथ विवाद से संबंधित रिकार्ड भूमिधारक तहसीलदार से तलब की जाती है परन्तु विवादित भूमि के संबंध में विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विद्वान जिला कलक्टर ने अपने एकपक्षीय आदेश दिनांक 27.9.2013 द्वारा अपीलांत व उसके पूर्वाधिकारियों के हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि को रेस्पो संख्या 2 के हक में हस्तांतरित कर दिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांत ने बहस में आगे कथन किया कि किसी भी सद्भाविक क्रेता/खातेदार के खातेदारी अधिकारों को प्रशासनिक आदेश के आधार पर बिना सुनवाई निरस्त नहीं किया जा सकता है । राजस्थान काश्त अधीन में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है । यह भी कथन किया कि अन्य भूमियों के साथ विवादित भूमि के संबंध में सहखातेदारों के मध्य राजस्व वाद संख्या 19/2007 एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार, अजमेर प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार संयोजित है जिससे तहसीलदार को उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रारंभ से जानकारी थी । इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलांघीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 27.9.2013 ग्राम लाडपुरा के खसरा नंबर 59 रकबा 0.13 हे० की हद तक निरस्त किये जाने के आदेश पारित करे ।
4. विद्वान वकील अपीलांत ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात अपीलांत की क्यशुदा खातेदारी की आराजियात है जिसके संबंध में विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्या०, अजमेर के न्यायालय में राजस्व वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण विचाराधीन होकर स्थगन आदेश आदिनांक प्रभावी है । विवादित भूमि में प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थी के हक, अधिकार निहित है । विद्वान जिलाधीश, अजमेर के आदेश दिनांक 27.9.2013 से प्रार्थी के हक व अधिकार प्रभावित हुए है जिससे वह पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांत को विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 14.8.2015 को अपनी खातेदारी भूमि की जमाबंदी की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त की तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि जानकारी कर आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर विधिक सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर ने रेस्पो० संख्या 2 को हस्तांतरित की है । हस्तांतरण आदेश की पालना में रेस्पो० संख्या 2 के नाम नामांतरण भी स्वीकृत हो चुका है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।
7. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में रेस्पो० संख्या 2 के नाम दर्ज है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होने से हस्तांतरित की है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।
8. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० का निस्तारण करना उचित समझते हैं । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विवादित आराजियात के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार रामी से विवादित भूमि क्रय की है जिसे सुना जाना आवश्यक था । अधी०न्याया० के आदेश से विवादित आराजियात रेस्पो० संख्या 2 के नाम हस्तांतरित किये जाने से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रकट होता है । अतः न्यायहित में हम अपीलांट को सुना जाना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
9. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने विवादित भूमि स्वयं की खातेदारी होने का कथन किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जिससे भी अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वर्किंग खाता संख्या 149 नया पुराना 160 के वर्किंग खसरा नंबर 719 रकबा 2-07-10, खसरा नंबर 43/1295 रकबा 00-16-10 किता 2 कुल रकबा 3-04-00 बीघा का मूल खातेदार मानसिंह रावत था । खातेदार मानसिंह रावत की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात जरिये नामांतरण संख्या 43 दिनांक 11.9.1998 से खातेदार मानसिंह की एकमात्र पुत्री रामी के नाम दर्ज हुई । श्रीमती रामी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के विवादित आराजियात का बेचान अपीलांट को किया । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बंदोबस्त विभाग ने खसरा नंबर 43/1295 रकबा 00-16-10 के नये नंबर 59 रकबा 0.13 है० कायम किये तथा उक्त खसरा नंबर को सिवायचक दर्ज कर दिया । चूंकि अपीलांट ने विवादित भूमि खातेदार रामी से क्रय की थी जिसे सुना जाना आवश्यक था । तत्पश्चात् विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश

दिनांक 27.9.2013 से विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तांतरित कर दी तथा वर्तमान में विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज है । जहां तक विवादित भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज होने का प्रश्न है चूंकि अपीलांट जरिये बयनामा कब्जे काशत में है । अधी0न्याया0 सहायक कलक्टर, मुख्या0, अजमेर ने उनके समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है । अतः इनका कब्जा होने के आधार पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को पक्षकार को सुना जाना जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 27.9.2013 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जान योग्य पाया जाता है ।

11. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ-12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013 ग्राम लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर के हाल खसरा नंबर 59 रकबा 0.13 है0 की हद तक अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

**राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर**

12. निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर**